



सत्यमेव जयते

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग

DEPARTMENT OF ADMINISTRATIVE REFORMS & PUBLIC GRIEVANCES



CPROGRAMS

MONTHLY REPORT

States/UTs

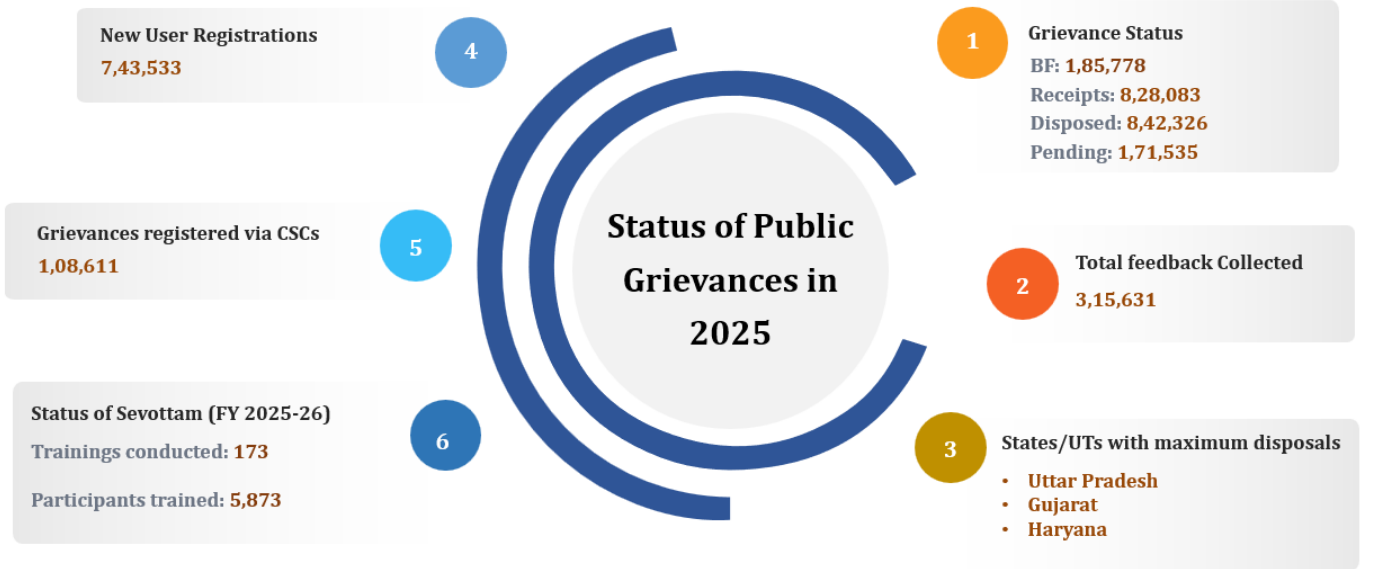
JANUARY 2026 Report Number 42

Department of Administrative Reforms and Public Grievances

विषयसूची

1. वर्ष 2025 एक नजर में	3
2. सारांश- जनवरी 2026.....	4
3. मुख्य-मुख्य बातें- जनवरी 2026	5
4. शिकायतों की समग्र स्थिति.....	6
5. फीडबैक कॉल सेंटर	7
6. नए प्रयोक्ताओं का पंजीकरण	9
7. जन सेवा केंद्र	10
8. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पोर्टल का एकीकरण	12
9. सेवोत्तम योजना	13
10. सेवोत्तम योजना पोर्टल	14
11. सफलता की कहानियां	16
12. मीडिया आउटरीच.....	18
अनुलग्नक	19

1. वर्ष 2025 एक नजर में



वर्ष 2025 की मुख्य-मुख्य बातें

- सुव्यवस्थित और वरिष्ठ स्तर पर शिकायतों की निगरानी को सुदृढ़ करने के लिए, **6 जून, 2025** को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर सीपीग्राम्स **समीक्षा मॉड्यूल** का शुभारंभ किया गया।
- डीएआरपीजी ने प्रभावशाली सर्वश्रेष्ठ परिपाटियों को प्रस्तुत करने वाली **"प्रभावी शिकायत निवारण: परिवर्तन की 100 कहानियाँ"** प्रकाशित कीं।
- सीपीग्राम्स प्लेटफॉर्म पर आउटरीच, जागरूकता और जुड़ाव बढ़ाने के लिए 2025 में **तीन सीएससी-लाइव सत्र** सफलतापूर्वक आयोजित किए गए।
- क्षमता विकास पहल को मजबूत करने के लिए, **सेवोत्तम दिशानिदेश 2025-26**, एक व्यापक मॉडल पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण सामग्री और एंड्रगॉजी के साथ विकसित किए गए थे।
- केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और राज्य प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों की भागीदारी के साथ, भोपाल (20 फरवरी 2025), तिरुवनंतपुरम (25 अप्रैल 2025), और नई दिल्ली (9 जुलाई 2025) में **"लोक शिकायतों के प्रभावी निवारण"** पर **राष्ट्रीय कार्यशालाएं** आयोजित की गईं, जिससे ज्ञान के आदान-प्रदान, सहयोग और शिकायत निवारण में सर्वोत्तम प्रथाओं के प्रसार की सुविधा मिली।

2. सारांश- जनवरी 2026

प्राप्त शिकायतें: 71,714

निपटान: 64,702

लंबित मामले: 1,78,674

प्रशिक्षण पाठ्यक्रम : 1,034

प्रशिक्षित अधिकारी: 34,812

(वि.वर्ष- 2022-26)



कुल प्राप्त: 13,605

अधिकतम: 8,331 (कर्नाटक)

कुल पंजीकरण: 67,728

अधिकतम: 11,172 (उत्तर प्रदेश)

3. मुख्य-मुख्य बातें- जनवरी 2026

सामान्य आकर्षण

01 1. अपर सचिव, डीएआरपीजी की अध्यक्षता में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और एटीआई के नोडल अधिकारियों के साथ **29 जनवरी, 2026** को एक मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

→ फीडबैक कॉल सेंटर ने जनवरी, 2026 में कुल **68,727 फीडबैक** एकत्र किए, जिसमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से **25,259 फीडबैक** एकत्र किए गए।

→ सेवोत्तम योजना के तहत, पिछले चार वित्तीय वर्ष (2022-23 से 2025-26) में **1,034 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम** पूरे किए गए हैं, जिनमें **~34,812 अधिकारियों** को प्रशिक्षण दिया गया है।

→ जनवरी, 2026 में, **सीएससी** के माध्यम से **कर्नाटक** में सबसे अधिक शिकायत पंजीकृत हुए। कुल **13,605** शिकायतों में से **कर्नाटक का योगदान कुल में लगभग 61 प्रतिशत** है।

सीपीग्राम्स पर लोक शिकायतों की स्थिति

02 → जनवरी, 2026 में, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित **71,714 लोक शिकायतें** प्राप्त हुईं और **64,702 लोक शिकायतों** का निवारण किया गया।

→ जनवरी, 2026 में **उत्तर प्रदेश** में सबसे अधिक 24,049 लोक शिकायतों का निवारण किया गया, इसके बाद **गुजरात** में 6,065 और **दिल्ली** में 4,624 लोक शिकायतों का निवारण किया गया।

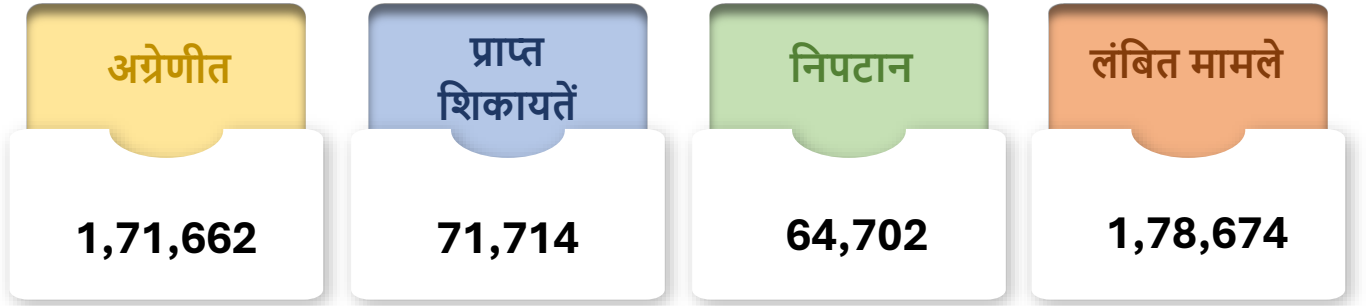
सीपीग्राम्स पर लोक शिकायतों के लंबित होने की स्थिति

03 → 31 जनवरी, 2026 तक **22** राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में **1000** से ज्यादा शिकायतें लंबित हैं।

→ 31 जनवरी, 2026 तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में **1,78,674** लोक शिकायत मामले लंबित हैं।

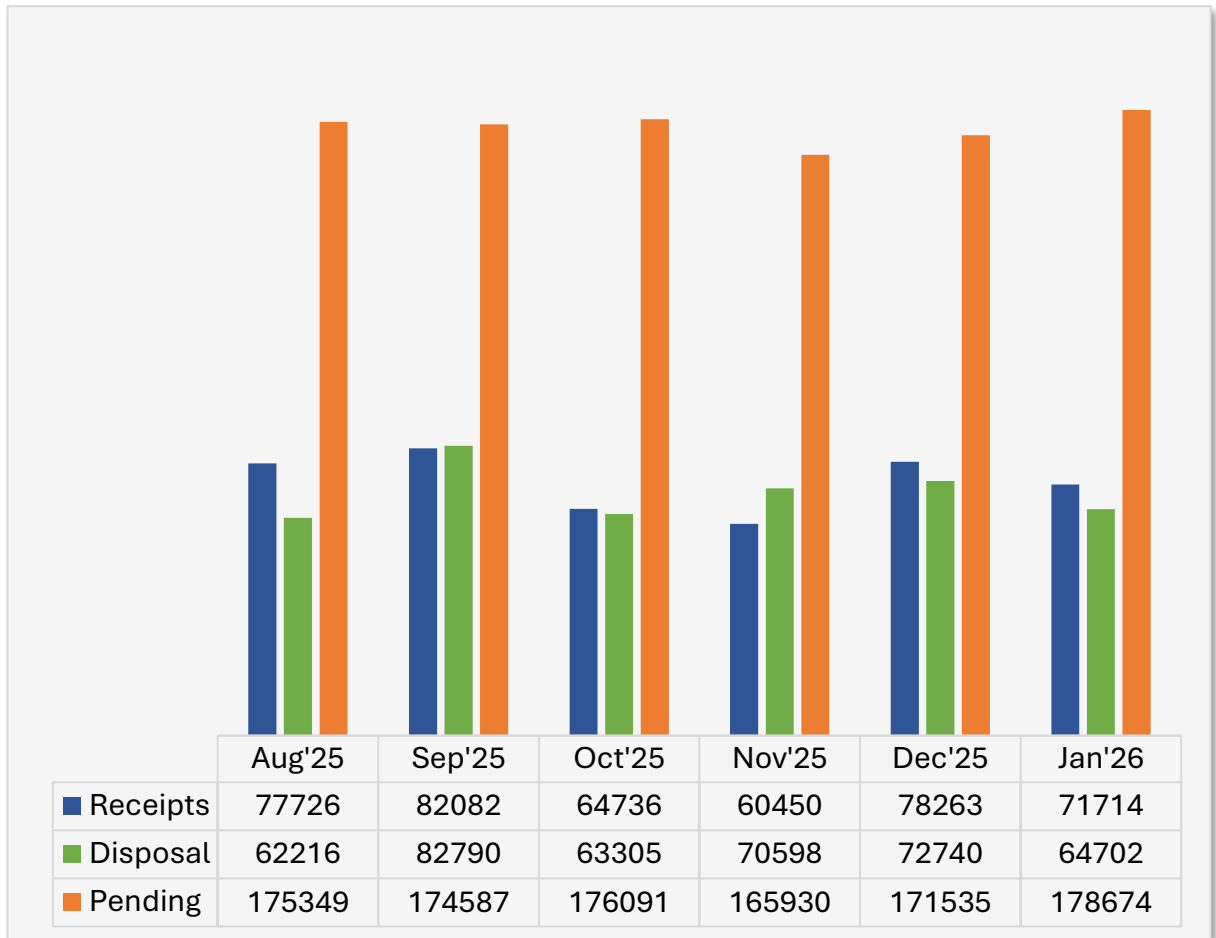
4. शिकायतों की समग्र स्थिति

अवलोकन



(समयावधि: दिनांक 01/01/2026 से 31/01/2026)

शिकायतों की माह-वार स्थिति



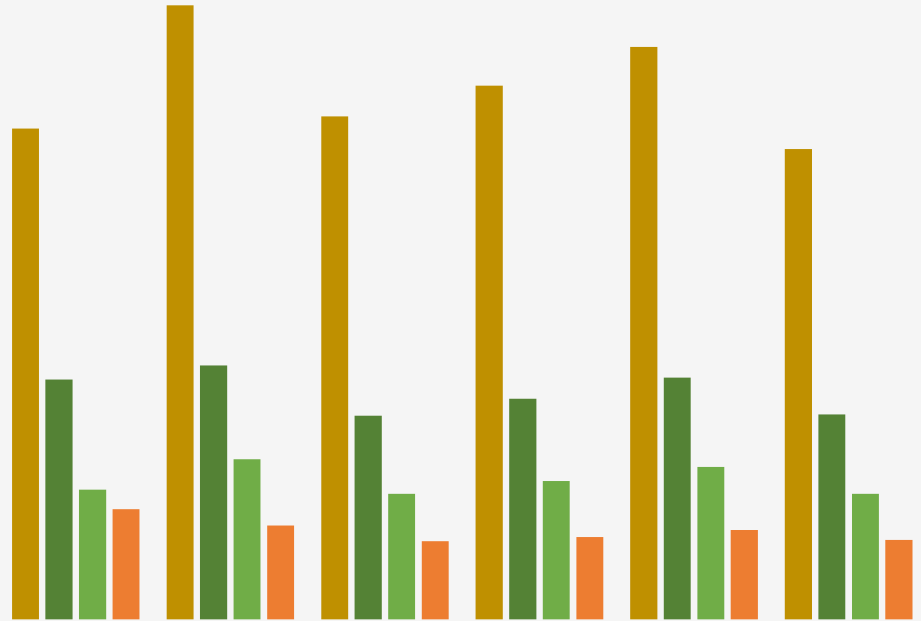
5. फीडबैक कॉल सेंटर

अवलोकन

1 जनवरी, 2026 से 31 जनवरी, 2026 की अवधि के दौरान, कुल 68,727 फीडबैक में से कॉल सेंटर के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 25,259 फीडबैक प्राप्त हुए। कुल 11,012 लोक शिकायतों को “निवारण कर दिया गया” के रूप में चिह्नित किया गया - जो 44 प्रतिशत से अधिक की निपटान दर को दर्शाता है। निपटाए गए मामलों में से, 61% से अधिक नागरिकों ने निवारण पर संतोष व्यक्त किया।

नीचे दिया गया कॉलम चार्ट अगस्त, 2025 से जनवरी, 2026 तक कॉल सेंटर फीडबैक से संबंधित चार प्रमुख मेट्रिक्स प्रस्तुत करता है: प्राप्त कुल फीडबैक, “निवारण कर दिया गया” के रूप में चिह्नित शिकायतें, और निवारण पर नागरिक संतुष्टि और असंतोष के स्तर

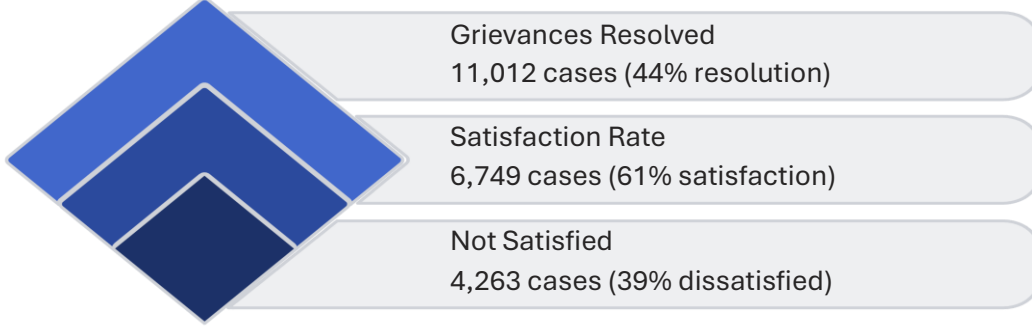
फीडबैक का माह-वार विश्लेषण



	Aug-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25	Dec-25	Jan-26
Feedback- States/UTs	26364	32982	27011	28669	30755	25259
Resolved	12878	13635	10939	11855	12977	11012
Satisfied	6961	8595	6736	7438	8186	6749
Not Satisfied	5917	5040	4203	4417	4791	4263

नीचे दर्शाया गया स्नैपशॉट जनवरी, 2026 में कॉल सेंटर के माध्यम से निपटाए गए 11,012 मामलों को दर्शाता है :

जनवरी में फीडबैक-संक्षेप में



कुल फीडबैक = निपटान + जिनका निपटान नहीं हो सका
निपटान = संतुष्ट + संतुष्ट नहीं

फीडबैक स्टेटस: शीर्ष 10 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र – जनवरी, 2026

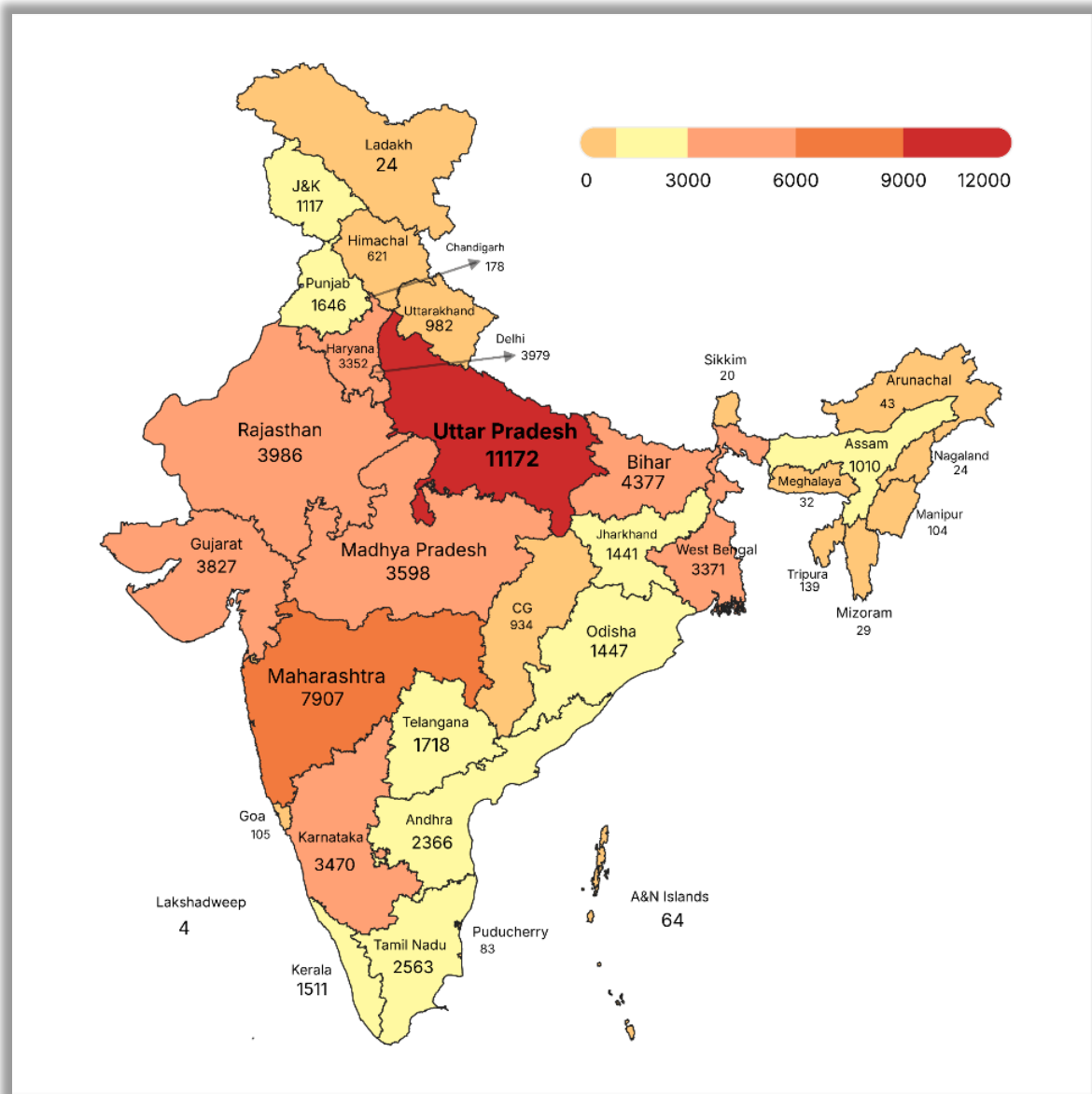
समाधान पर प्राप्त फीडबैक की उच्चतम संख्या और उनकी संतुष्टि की स्थिति (घटते हुए क्रम में रैंक) वाले शीर्ष 10 राज्य और संघ राज्य क्षेत्र:

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल शिकायतों का निवारण	संतुष्ट	असंतुष्ट
1	उत्तर प्रदेश सरकार	5171	2783	54%
2	गुजरात सरकार	810	552	68%
3	मध्य प्रदेश सरकार	612	465	76%
4	बिहार सरकार	582	387	66%
5	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	581	353	61%
6	हरियाणा सरकार	561	373	66%
7	राजस्थान सरकार	439	287	65%
8	महाराष्ट्र सरकार	434	288	66%
9	कर्नाटक सरकार	286	225	79%
10	उत्तराखंड सरकार	275	159	58%

6. नए उपभोक्ताओं का पंजीकरण

जनवरी, 2026 में विभिन्न चैनलों के माध्यम से सीपीग्राम्स पर कुल **67,728** नए प्रयोक्ताओं ने पंजीकरण कराया है, जिनमें से **11,172** पंजीकरण उत्तर प्रदेश से हैं।

जनवरी, 2026 में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से सीपीग्राम्स पर नए प्रयोक्ताओं का पंजीकरण



7. जन सेवा केंद्र

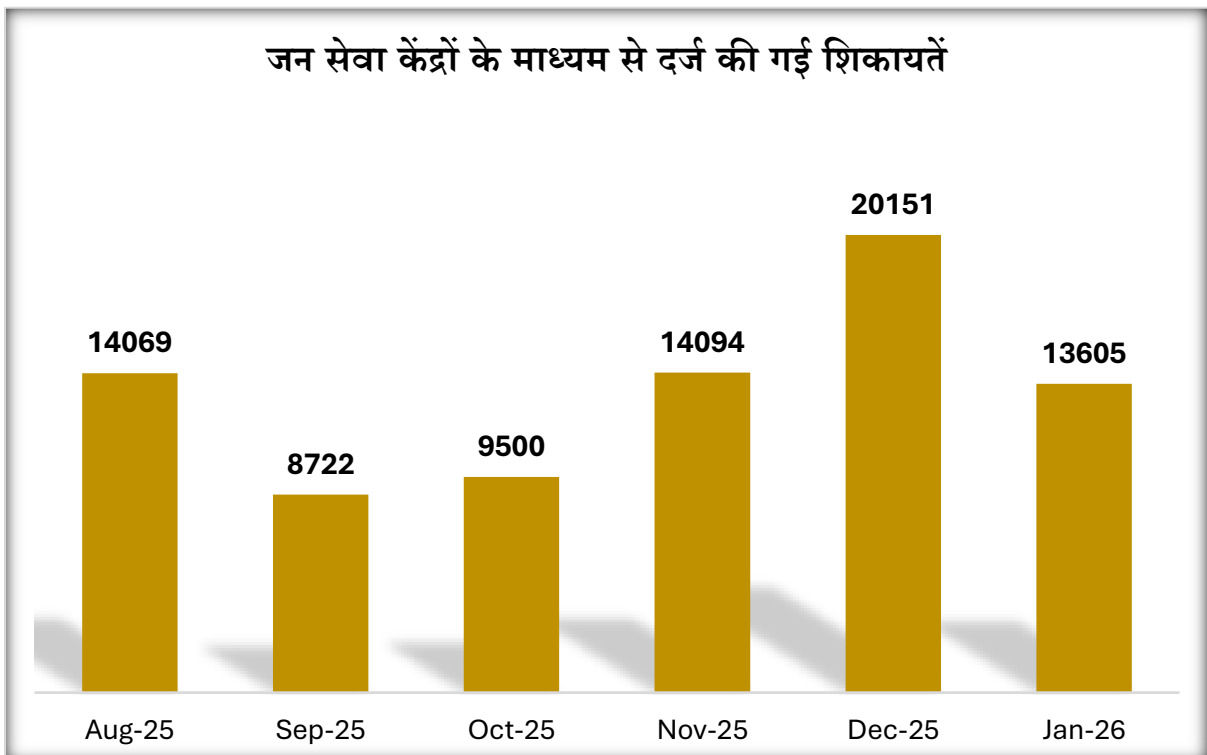
सीपीग्राम्स को जन सेवा केंद्रों (सीएससी) पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है और यह 2.5 लाख ग्राम स्तरीय उद्यमियों (वीएलई) के साथ जुड़कर 5 लाख से अधिक सीएससी पर उपलब्ध है।



(समयावधि: दिनांक 01/01/2026 से 31/01/2026)

जन सेवा केंद्रों के माध्यम से दर्ज शिकायतों का अवलोकन

जन सेवा केंद्रों (सीएससी) के माध्यम से, जनवरी, 2026 में कुल 13,605 शिकायतें दर्ज की गईं।

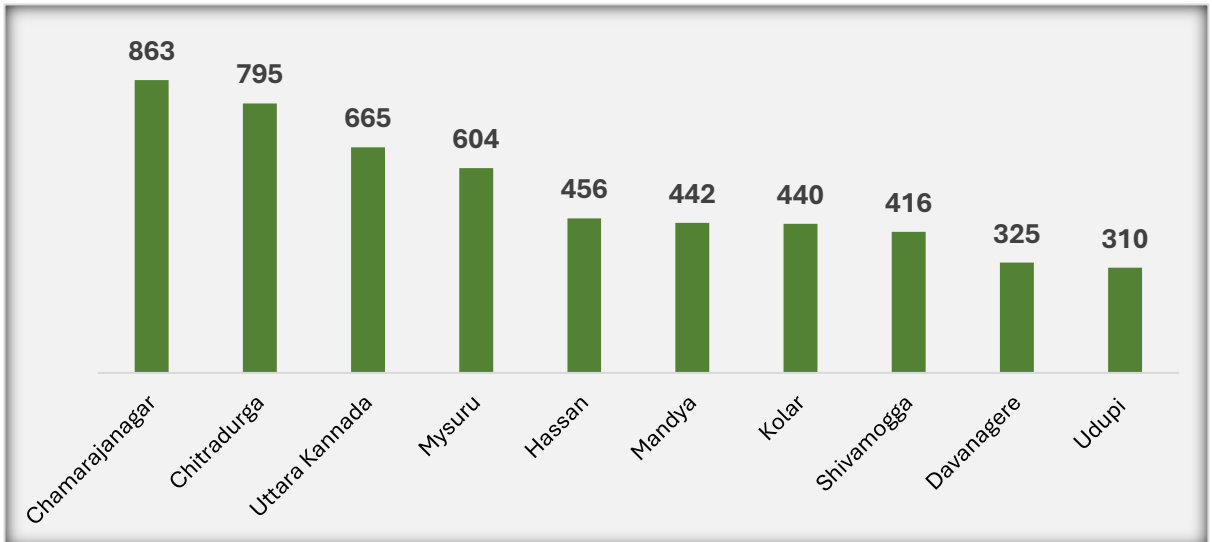


शीर्ष 3 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र : जनवरी, 2026 में सीएससी में शीर्ष स्तरीय श्रेणी-वार शिकायत वितरण

राज्य	कुल प्राप्त शिकायतें	शीर्ष स्तर की श्रेणी	प्राप्त %
कर्नाटक	8331	योजनाएँ	21%
		मोबाइल संबंधी	19%
		ऋण/सब्सिडी और विलंबित भुगतान संबंधी	8%
		प्रशिक्षण संबंधी मामले	5%
		टावर संबंधी	3%
उत्तर प्रदेश	2029	सार्वजनिक वितरण प्रणाली संबंधी	17%
		पीएम किसान संबंधी मुद्दे	9%
		आधार अपडेट	7%
		कर्मचारी भविष्य निधि संगठन	3%
		ग्राहक सेवा संबंधी	3%
बिहार	471	सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित	21%
		एलपीजी/एलपीजी एजेंसी से संबंधित	18%
		कर्मचारी भविष्य निधि संगठन	6%
		ग्राहक सेवा से संबंधित	6%
		पीएम किसान से संबंधित मुद्दे	5%

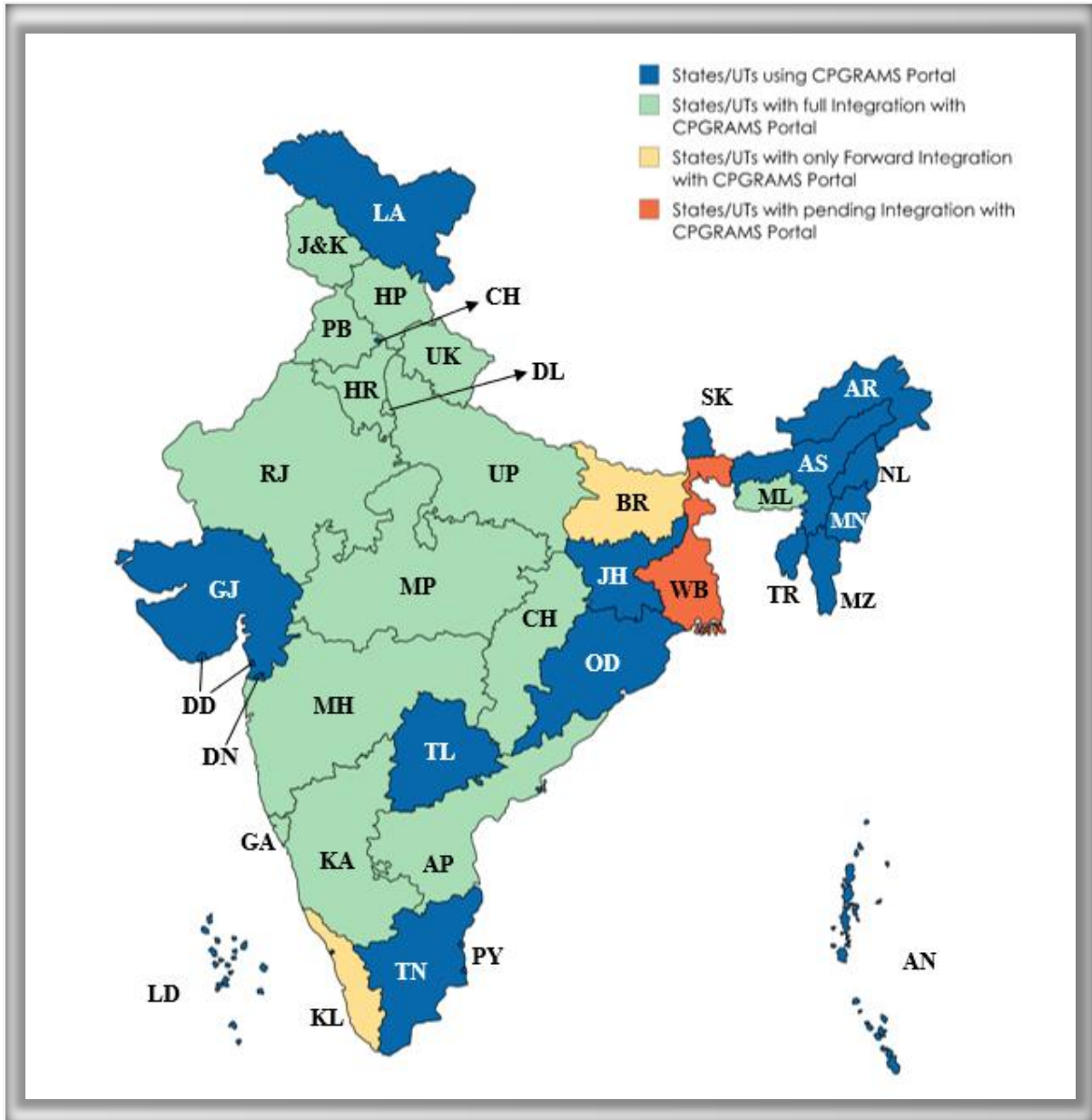
कर्नाटक: जनवरी 2026 में जिला स्तर पर शिकायत वितरण

शिकायतों के पंजीकरण के मामले में कर्नाटक सबसे आगे है, जहां सीएससी के माध्यम से दर्ज कुल शिकायतों में से 61% शिकायतें दर्ज हुई हैं।



8. राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के पोर्टलों का एकीकरण

वन नेशन-वन पोर्टल विजन के तहत, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने सभी संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के शिकायत पोर्टलों को सीपीग्राम्स के साथ एकीकृत करने का एक व्यापक कार्य किया है।



9. सेवोत्तम योजना

क्षमता विकास के एक प्रमुख प्रयास में, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग "सेवोत्तम योजना" को लागू करता है, जिसके तहत विभाग राज्य सरकारों के शिकायत निवारण अधिकारियों के क्षमता विकास के लिए एटीआई में एक सेवोत्तम प्रशिक्षण प्रकोष्ठ की स्थापना के लिए राज्य एटीआई/सीटीआई को वित्त पोषित करता है।

विभाग द्वारा 3 जुलाई, 2024 को जारी सेवोत्तम योजना के संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, सेवोत्तम मॉडल और शिकायत निवारण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए राज्य एटीआई को प्रति प्रतिभागी प्रति दिन 1500 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान प्राप्त करने वाले एटीआई

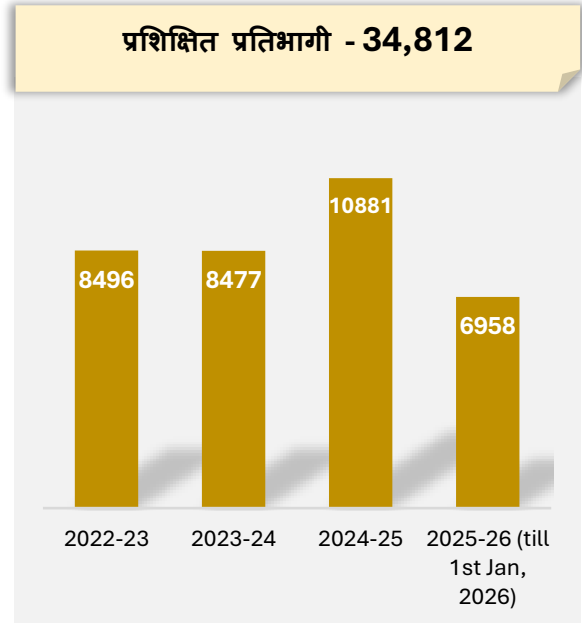
वित्त वर्ष 2025-26 के लिए निम्नलिखित 22 एटीआई से प्राप्त प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है और अनुदान, उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) प्राप्ति के आधार पर किस्तों में जारी किया जा रहा है:



नोट: सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध है कि वे वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए उपयोगिता प्रमाणपत्र (यूसी) और प्रस्ताव/प्रशिक्षण कैलेंडर जल्द से जल्द प्रस्तुत करें ताकि डीएआरपीजी अनुदान की अगली किस्त जारी कर सके।

10. सेवोत्तम योजना पोर्टल

पिछले चार वित्तीय वर्ष में आयोजित प्रशिक्षणों और प्रशिक्षित प्रतिभागियों का अवलोकन



जनवरी, 2026 में आयोजित प्रशिक्षण सत्रों के प्रमुख क्षण



महात्मा गांधी राज्य लोक प्रशासन संस्थान
(एमजीएसआईपीए)

डॉ. एमसीआर एचआरडी इंस्टीट्यूट,
हैदराबाद



वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्यों द्वारा साझा किए गए पाठ्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण:

क्र.सं.	राज्य	एटीआई का नाम	पाठ्यक्रम/प्रशिक्षण कार्यक्रम	प्रशिक्षित प्रतिभागी
1	आंध्र प्रदेश	मानव संसाधन विकास संस्थान	52	1745
2	हरियाणा	हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान (एचआईपीए), गुरुग्राम	50	1724
3	तमिलनाडु	अन्ना प्रशासनिक कर्मचारी महाविद्यालय	22	993
4	तेलंगाना	डॉ. एमसीआर मानव संसाधन विकास संस्थान, हैदराबाद	16	488
5	पंजाब	महात्मा गांधी राज्य लोक प्रशासन संस्थान (एमजीएसआईपीए)	13	380
6	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान (एचपीआईपीए), शिमला	11	247
7	केरल	केरल सरकारी प्रबंधन संस्थान (आईएमजी), तिरुवनंतपुरम	11	485
8	मध्य प्रदेश	आरसीवीपी नोरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी, भोपाल	10	395
9	मेघालय	मेघालय प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान (एमएटीआई), शिलांग	6	162
10	राजस्थान	एचसीएम राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान (एचसीएम, आरआईपीए), जयपुर	6	168
11	उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी (यूपीएएएम), लखनऊ	2	171
		कुल	199	6958

नोट: सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के एटीआई से अनुरोध है कि वे सेवोत्तम योजना पोर्टल [<https://ati.darpg.in.net/login/>] पर आयोजित प्रशिक्षण/ प्रशिक्षित प्रतिभागी और चल रहे पाठ्यक्रमों की स्थिति को अपडेट करें।

11. सफलता की कहानियां

जलापूर्ति की बहाली

श्री भीम सिंह यादव की शिकायत

श्री भीम सिंह यादव ने संबंधित प्राधिकरण द्वारा बिजली बिलों का भुगतान न करने के कारण जलापूर्ति ट्यूबवेल के बिजली मीटर को हटाने के कारण मलेर्ना गांव में पानी की आपूर्ति बाधित होने की शिकायत की, जिससे ग्रामीणों को कठिनाई होती है। समाधान की मांग करते हुए, उन्होंने सीपीग्राम्स पोर्टल पर एक शिकायत दर्ज कराते हुए पानी की आपूर्ति की तत्काल बहाली का अनुरोध किया। संबंधित अधिकारियों ने मामले की समीक्षा की और बताया कि बिजली मीटर को फिर से स्थापित किया गया है और पानी की आपूर्ति बहाल कर दी गई है, जिससे शिकायत का समाधान हो गया है।

श्री कनिष्क गुप्ता की शिकायत

सड़क का रखरखाव

श्री कनिष्क गुप्ता गुरुग्राम में एक सड़क की खराब स्थिति से परेशान थे, जिसकी शिकायत उन्होंने सीपीग्राम्स पोर्टल पर की। शिकायत दर्ज होने के बाद, सीपीग्राम्स ने उचित कार्रवाई के लिए संबंधित केंद्रीय, राज्य और स्थानीय अधिकारियों में इसके हस्तांतरण और जांच की सुविधा प्रदान की। सीपीग्राम्स द्वारा सक्षम निरंतर अनुवर्ती कार्रवाई और समन्वय के माध्यम से, शिकायत को अंततः नगर निगम द्वारा देखा गया। आवश्यक कार्रवाई की गई, मुद्दे का समाधान किया गया और शिकायतकर्ता ने समाधान पर संतोष व्यक्त किया।

श्री सुमित धारीवाल की शिकायत

श्री सुमित धारीवाल ने बताया कि गुरुग्राम के एनएच-48 पर बिलासपुर चौक पर पानी जमा हो रहा था, जिससे नालियों के जाम होने और अपर्याप्त जल निकासी के कारण निवासियों और दुकानदारों को भारी असुविधा हो रही थी। समाधान की मांग करते हुए, उन्होंने सीपीग्राम्स पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई। संबंधित अधिकारियों ने मामले की समीक्षा की और जमा पानी को निकालने के लिए कर्मचारियों और मशीनरी को तैनात किया। जल निकासी की उचित व्यवस्था की गई थी, और विशेष रूप से वर्षा के दौरान पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्षेत्र की नियमित रूप से निगरानी की जा रही है, जिससे शिकायत का समाधान हो सके।

**जल भराव की
समस्या का
समाधान**

अधिक टोल वसूली की शिकायत

श्री कैलाश शर्मा की शिकायत

श्री कैलाश शर्मा ने दौसा जिले के गाजीपुर टोल प्लाजा पर टोल कर्मचारियों द्वारा लागू श्रेणी के वैध फास्टैग के बावजूद अपने एलसीवी वाहन से जबरन अतिरिक्त टोल वसूलने और अन्य श्रेणी के लिए अधिक टोल वसूलने का मुद्दा उठाया। उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि टोल प्लाजा पर फास्टैग का उपयोग नहीं किया जा रहा था और भुगतान नकद में लिया जा रहा था, जिससे उन्हें और अन्य प्रभावित वाहन मालिकों को बार-बार अधिक शुल्क लिया जा रहा था। समाधान की मांग करते हुए, उन्होंने सीपीग्राम्स पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई। संबंधित अधिकारियों ने मामले की समीक्षा की और टोल रियायत पाने वाले पर प्रतिबंध लगा दिया, जिससे शिकायत का समाधान हो गया।

12. मीडिया आउटरीच

DARPG @DARPG_GoI

DARPG has released its 41st #CPGRAMS Monthly Report for December, 2025, for States/UTs.

- In December, 2025, 78,263 PG cases were received for the States/UTs and 72,740 PG cases were redressed.
- There has been a rise in the disposal of PG cases, rising from 70,598 in November to 72,740 in December.

Full report can be accessed on: darp.gov.in/sites/default/...

#CPGRAMS #GoodGovernance #GrievanceRedressal #CitizenFirst #DigitalIndia #PublicService

@narendramodi | @PMOIndia | @DrJitendraSingh | @MIB_India | @PIB_India | @DDNewslive | @aimnewsalerts | @mygovindia

Last edited 2:55 PM - Jan 23, 2026 - 431 Views

DARPG @DARPG_GoI

DARPG conducted a virtual meeting with the Administrative Training Institutes (ATIs) of all States and Union Territories. Shri Puneet Yadav, Additional Secretary, DARPG, chaired the meeting. He stressed upon the importance of #Sevottam Training, across the States & UTs, in progressing the cause of quality disposal of public grievances by the concerned Grievance Redressal Officers (GROs) and Nodal officers.

#GoodGovernance #DigitalIndia #CPGRAMS #Sevottam #PublicGrievanceRedressal #CapacityBuilding

@DARPG_GoI @DARPGIndia @darpgoi @DARPG_GoI www.darp.gov.in

DARPG @DARPG_GoI

Shri Puneet Yadav, Additional Secretary, DARPG, chaired the monthly #CPGRAMS review meeting with Nodal Grievance Redressal Officers of States/UTs and representatives of Administrative Training Institutes (ATIs). States/UTs were urged to reduce pendency and improve grievance closure timelines to ensure more efficient and timely redressal.

#CPGRAMSUpdate #CitizenFirst #GrievanceRedressal #GoodGovernance #Sevottam

Narendra Modi and 7 others

अनुलग्नक

अनुलग्नक 1: राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का कार्य-निष्पादन – जनवरी, 2026

अनुलग्नक 1.1: प्राप्त शिकायतों की अधिकतम संख्या – जनवरी, 2026

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	अप्रेणीत	प्राप्त शिकायतें	कुल शिकायतें	निपटान	लंबित
1	उत्तर प्रदेश सरकार	20735	25657	46392	24049	22343
2	गुजरात सरकार	5210	5053	10263	6065	4198
3	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	5422	3926	9348	4624	4724
4	महाराष्ट्र सरकार	29832	3874	33706	3123	30583
5	हरियाणा सरकार	8507	3870	12377	3533	8844
6	बिहार सरकार	11885	3825	15710	3152	12558
7	मध्य प्रदेश सरकार	10394	3394	13788	2584	11204
8	राजस्थान सरकार	2457	3141	5598	2250	3348
9	कर्नाटक सरकार	8508	3127	11635	3483	8152
10	तमिलनाडु सरकार	8087	2251	10338	1814	8524

अनुलग्नक 1.2: निपटान की अधिकतम संख्या – जनवरी, 2026

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	अप्रेणीत	प्राप्त शिकायतें	कुल शिकायतें	निपटान	लंबित
1	उत्तर प्रदेश सरकार	20735	25657	46392	24049	22343
2	गुजरात सरकार	5210	5053	10263	6065	4198
3	दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी सरकार	5422	3926	9348	4624	4724
4	हरियाणा सरकार	8507	3870	12377	3533	8844
5	कर्नाटक सरकार	8508	3127	11635	3483	8152
6	बिहार सरकार	11885	3825	15710	3152	12558

7	महाराष्ट्र सरकार	29832	3874	33706	3123	30583
8	मध्य प्रदेश सरकार	10394	3394	13788	2584	11204
9	राजस्थान सरकार	2457	3141	5598	2250	3348
10	तमिलनाडु सरकार	8087	2251	10338	1814	8524

अनुलग्नक 2: राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का कार्य-निष्पादन - 1 जनवरी से 31 जनवरी, 2026

अनुलग्नक 2.1 1000 से अधिक लंबित शिकायतों वाले राज्य/संघ राज्य क्षेत्र - 1 जनवरी से 31 जनवरी, 2026

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	अग्रेणीत	प्राप्त शिकायतें	कुल शिकायतें	निपटान	लंबित
1	महाराष्ट्र सरकार	29832	3874	33706	3123	30583
2	उत्तर प्रदेश सरकार	20735	25657	46392	24049	22343
3	बिहार सरकार	11885	3825	15710	3152	12558
4	मध्य प्रदेश सरकार	10394	3394	13788	2584	11204
5	ओडिशा सरकार	10828	1621	12449	1676	10773
6	हरियाणा सरकार	8507	3870	12377	3533	8844
7	तमिलनाडु सरकार	8087	2251	10338	1814	8524
8	कर्नाटक सरकार	8508	3127	11635	3483	8152
9	हिमाचल प्रदेश सरकार	6825	338	7163	203	6960
10	छत्तीसगढ़ सरकार	5547	1110	6657	537	6120
11	जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश सरकार	5597	754	6351	253	6098
12	पंजाब सरकार	5478	1196	6674	933	5741
13	आंध्र प्रदेश सरकार	4424	1528	5952	1031	4921
14	दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी सरकार	5422	3926	9348	4624	4724
15	झारखंड सरकार	3520	1357	4877	658	4219
16	गुजरात सरकार	5210	5053	10263	6065	4198

17	राजस्थान सरकार	2457	3141	5598	2250	3348
18	असम सरकार	2430	617	3047	381	2666
19	उत्तराखंड सरकार	1611	1204	2815	1462	1353
20	मणिपुर सरकार	1297	39	1336	4	1332
21	नागालैंड सरकार	1321	5	1326	0	1326

अनुलग्नक 2.2: अधिकतम लंबित प्रतिशत (पूर्वोत्तर राज्य) - 1 जनवरी से 31 जनवरी, 2026

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	अग्रेणीत	प्राप्त शिकायतें	कुल शिकायतें	निपटान	लंबित	एसीटी (दिनों में)	% लंबित
1	नागालैंड सरकार	1321	5	1326	0	1326	60	100.00%
2	मणिपुर सरकार	1297	39	1336	4	1332	60	99.70%
3	मेघालय सरकार	263	12	275	2	273	102	99.27%
4	अरुणाचल प्रदेश सरकार	246	28	274	12	262	6	95.62%
5	असम सरकार	2430	617	3047	381	2666	75	87.50%
6	सिक्किम सरकार	28	6	34	11	23	59	67.65%
7	त्रिपुरा सरकार	65	127	192	87	105	13	54.69%
8	मिजोरम सरकार	93	7	100	62	38	399	38.00%

अनुलग्नक 2.3: 21 दिनों से अधिक समय से लंबित शिकायतों वाले शीर्ष 10 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र - 1 जनवरी से 31 जनवरी, 2026

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	अग्रेणीत	प्राप्त शिकायतें	कुल शिकायतें	निपटान	लंबित	लंबित > 21 दिन
1	महाराष्ट्र सरकार	18757	46266	65023	35191	29832	27958
2	ओडिशा सरकार	18363	17445	35808	24983	10825	10051
3	बिहार सरकार	7860	39200	47060	35177	11883	10046
4	मध्य प्रदेश सरकार	3592	41216	44808	34413	10395	9174

5	उत्तर प्रदेश सरकार	12272	304907	317179	296444	20735	7578
6	तमिलनाडु सरकार	7896	24207	32103	24015	8088	7198
7	हिमाचल प्रदेश सरकार	5711	3593	9304	2480	6824	6748
8	हरियाणा सरकार	11067	42115	53182	44678	8504	6716
9	कर्नाटक सरकार	5320	24712	30032	21517	8515	6455
10	जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र सरकार	7339	7936	15275	9678	5597	5564

अनुलग्नक 2.4: कम औसत समापन समय वाले राज्य/संघ राज्य क्षेत्र – 1 जनवरी से 31 जनवरी, 2026

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	कुल निपटान	औसत निवारण समय (दिनों में)
1	तमिलनाडु सरकार	1814	4
2	उत्तराखंड सरकार	1462	5
3	अरुणाचल प्रदेश सरकार	12	6
4	त्रिपुरा सरकार	87	13
5	तेलंगाना सरकार	864	14
6	अंडमान और निकोबार सरकार	89	14
7	लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र सरकार	13	20
8	पंजाब सरकार	933	26
9	ओडिशा सरकार	1676	31
10	गुजरात सरकार	6065	32



प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग

भारत सरकार

सरदार पटेल भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110001